International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 16 Issue 06, June 2026,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081 UGC Approved Journal Number: 48887
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

भारत में नक्सलवाद का अंत: एक निर्णायक युग का समापन (2026 तक का विस्तृत, रणनीतिक एवं संसदीय विश्लेषण)

Auther 1: देवा कुमार गोंड, शोध छात्र, राजनीतिशास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज
Auther 2:डॉक्टर विजय कुमार राय, प्रोफेसर,राजनीतिशाश्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज

भारत के आधुनिक इतिहास में वामपंथी उग्रवाद (LWE) या नक्सलवाद एक ऐसा नासूर रहा है, जिसने न केवल देश की आंतरिक सुरक्षा को गंभीर रूप से खतरे में डाला, बल्कि लोकतांत्रिक ताने-बाने और विकास की अवधारणा को भी पंगु बनाए रखा। वर्ष 1967 में पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव 'नक्सलबाड़ी' से भूमि सुधारों और शोषित किसानों के हक के नाम पर भड़का यह असंतोष, समय के साथ अपनी वैचारिक दिशा खोकर एक क्रूर सशस्त्र उग्रवाद में तब्दील हो गया। 'सत्ता बंदूक की नली से निकलती है' के माओवादी सिद्धांत पर चलने वाले इस आंदोलन ने भारत के हृदय स्थल में एक विशाल **'लाल गलियारे' (Red Corridor)** का निर्माण कर लिया था, जो एक समय पशुपतिनाथ (नेपाल) से लेकर तिरुपति (आंध्र प्रदेश) तक फैला हुआ था।

दशकों तक इस हिंसा ने देश के सबसे पिछड़े और जनजातीय बहुल क्षेत्रों को विकास से महरुम रखा। तत्कालीन नीतिगत शिथिलता और 'विकासात्मक बनाम सैन्य दृष्टिकोण' के अंतर्विरोधों के कारण यह समस्या एक अंतहीन दुष्चक्र बन चुकी थी। एक समय इसे देश की संप्रभुता के लिए 'सबसे बड़ा आंतरिक खतरा' माना गया, जिसने सुरक्षा बलों के मनोबल और राज्य की इकबालिया ताकत को बार-बार चुनौती दी।

नीतिगत बदलाव और निर्णायक मोड़

वर्ष 2014 के बाद भारत सरकार ने इस चुनौती के प्रति अपनी रणनीति में एक युगांतकारी और आक्रामक बदलाव (Paradigm Shift) किया। ढुलमुल और केवल सुरक्षात्मक रवैये को त्यागकर, केंद्र सरकार ने "**जीरो टॉलरेंस**" की नीति अपनाई। गृह मंत्रालय के नेतृत्व में सैन्य आक्रामकता, अत्याधुनिक खुफिया तंत्र, अंतर-राज्यीय समन्वय और अंतिम छोर तक कल्याणकारी योजनाओं के समावेशन का एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया गया, जिसने माओवादियों की वैचारिक और भौतिक दोनों रीढ़ तोड़ दी।

वर्तमान में **मई 2026** तक आते-आते, यह खूनी आंदोलन अपने अंत के ऐतिहासिक मुकाम पर पहुंच चुका है। केंद्र सरकार द्वारा पूरी दृढ़ता के साथ निर्धारित की गई **31 मार्च 2026 की अंतिम समयसीमा (Deadline)** तक वामपंथी उग्रवाद को उसके अंतिम गढ़ों—छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़, बीजापुर और सुकमा के घने जंगलों—में पूरी तरह निष्प्रभावी कर दिया गया है। संसद के पटल पर गूंजने वाले हालिया आंकड़ों और नीतिगत बहसों के आलोक में, यह लेख इस बात का विस्तृत और प्रामाणिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है कि कैसे भारत ने अपने इस सबसे लंबे आंतरिक सुरक्षा संकट पर विजय प्राप्त कर एक 'नक्सल-मुक्त' और सुरक्षित राष्ट्र के नए युग में प्रवेश किया है।

1. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: वैचारिक उग्रवाद से आतंक का सफर

नक्सलवाद की शुरुआत 1960 के दशक के उत्तरार्ध में पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव **नक्सलबाड़ी** से हुई थी। **चारु मजूमदार** और **कानू सान्याल** के नेतृत्व में शुरू हुआ यह आंदोलन शुरुआत में भूमिहीन किसानों और आदिवासियों के हक की लड़ाई के रूप में प्रस्तुत किया गया। लेकिन जल्द ही सीपीआई (माओवादी) जैसे प्रतिबंधित संगठनों ने इसे देश के खिलाफ एक हिंसक हथकंडे में तब्दील कर दिया।

माओवादियों का मुख्य उद्देश्य भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को 'अर्ध-औपनिवेशिक' और 'अर्ध-सामंती' बताकर सशस्त्र क्रांति (Armed Rebellion) के जरिए उखाड़ फेंकना था। उन्होंने देश के भौगोलिक रूप से दुर्गम क्षेत्रों (जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और महाराष्ट्र के घने जंगलों) को अपना ठिकाना बनाया। वहां बुनियादी

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 16 Issue 06, June 2026,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081 UGC Approved Journal Number: 48887
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

सुविधाओं की कमी और विकास के अभाव का फायदा उठाकर आदिवासियों को मोहरा बनाया और अपनी एक हिंसक 'समांतर सरकार' (Janatana Sarkar) खड़ी कर ली।

2. आंतरिक सुरक्षा और विकास पर आघात: एक दुष्चक्र

एक समय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नक्सलवाद को *"देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा"* कहा था। दशकों तक इस आंदोलन ने भारत को गहरे घाव दिए:

- **विकास विरोधी तंत्र:** माओवादियों का मुख्य एजेंडा ही विकास को रोकना था। उन्होंने सुदूर क्षेत्रों में बनने वाली सड़कों, स्कूलों, मोबाइल टावरों और अस्पतालों को बार-बार बम से उड़ाया ताकि स्थानीय जनता तक सरकार न पहुंच सके।
- **आर्थिक रीढ़ पर चोट:** खनिज-समृद्ध क्षेत्रों (बस्तर, दंतेवाड़ा आदि) में खनन कार्यों और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को निशाना बनाकर देश को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया।
- **मानवीय त्रासदी:** सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस खूनी संघर्ष में 4,000 से अधिक निर्दोष नागरिकों और लगभग 2,700 से अधिक वीर सुरक्षाकर्मियों को अपनी जान गंवानी पड़ी।

3. केंद्र सरकार की निर्णायक रणनीति: बहुआयामी 'एक्शन प्लान'

वर्ष 2014 के बाद और विशेष रूप से पिछले 3-4 वर्षों में, भारत सरकार ने पुरानी रक्षात्मक और ढुलमुल नीतियों को पूरी तरह बदल दिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लागू की गई **'समाधान' (SAMADHAN)** नीति और '**नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान**' ने इस लड़ाई का पासा पलट दिया।

S - Smart Leadership (कुशल नेतृत्व)
A - Aggressive Strategy (आक्रामक रणनीति)
M - Motivation and Training (उत्साह और आधुनिक प्रशिक्षण)
A - Actionable Intelligence (सटीक खुफिया जानकारी)
D - Dashboard for KPIs (डेटा-संचालित निगरानी)
H - Harnessing Technology (तकनीक - ड्रोन, GPS, सैटेलाइट का उपयोग)
A - Action Plan for Each Theatre (हर क्षेत्र के लिए अलग रणनीति)
N - No Access to Financing (नक्सली वित्तपोषण पर पूर्ण रोक)

केंद्रीय सरकार के हालिया विशिष्ट एक्शन प्लान (2025-2026):

1. **सुरक्षा वैक्यूम को भरना (Fortified Security Camps):** पिछले 6 वर्षों में जंगलों के भीतर **361 से अधिक नए सुरक्षा कैंप** स्थापित किए गए हैं। केंद्रीय बलों (CRPF, CoBRA) और राज्य पुलिस (DRG, बस्तर फाइटर्स) ने नक्सलियों के सुरक्षित गढ़ों में घुसकर 'फॉरवर्ड कैंप' बनाए हैं।
2. **अंतर-राज्यीय समन्वय (Inter-State Coordination):** माओवादी अक्सर एक राज्य में हमला कर दूसरे राज्य की सीमा में छिप जाते थे। सरकार ने संयुक्त ऑपरेशनों (जैसे 'ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट') के माध्यम से राज्यों की सीमाओं को सील कर नक्सलियों का घेराव किया।
3. **वित्तीय नेटवर्क को ध्वस्त करना (Choking Naxal Finance):** राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) में एक समर्पित वर्टिकल बनाकर और प्रवर्तन निदेशालय (ED) के साथ मिलकर नक्सलियों की उगाही और फंडिंग नेटवर्क को कुचल दिया गया। अब तक ₹100 करोड़ से अधिक की चल-अचल संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं।

4. आंकड़ों में नक्सलवाद का पतन: 2026 की जमीनी हकीकत

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 16 Issue 06, June 2026,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081 UGC Approved Journal Number: 48887
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

4. आंकड़ों में नक्सलवाद का पतन: ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और जमीनी हकीकत

वामपंथी उग्रवाद के पतन को केवल वर्तमान परिदृश्य से नहीं समझा जा सकता; इसके ऐतिहासिक उतार-चढ़ाव और आंकड़ों की पृष्ठभूमि इस बात की गवाही देती है कि भारत ने कितनी लंबी और कठिन लड़ाई जीती है।

ऐतिहासिक संदर्भ: 'रेड कॉरिडोर' का आतंक

एक समय था जब देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नक्सलवाद को भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए **"सबसे गंभीर अस्तित्वगत खतरा"** घोषित किया था। वर्ष 2000 के दशक के मध्य में, नेपाल के पशुपतिनाथ से लेकर आंध्र प्रदेश के तिरुपति तक एक विस्तृत **'लाल गलियारा' (Red Corridor)** आकार ले चुका था। तत्कालीन समय में खनिज संपन्न, जनजातीय बहुल और दुर्गम वनों से घिरे भारत के लगभग एक-तिहाई हिस्से पर भारतीय राज्य की संप्रभुता को सीधी चुनौती मिल रही थी। माओवादियों ने सुरक्षा बलों के खिलाफ घातक 'एम्बुश' (घात लगाकर हमला) की रणनीति अपनाई, जिसके परिणामस्वरूप 2010 में दंतेवाड़ा में हुआ भीषण हमला (जिसमें 76 जवान शहीद हुए थे) भारतीय इतिहास के सबसे काले अध्यायों में दर्ज हुआ।

आंकड़ों की पृष्ठभूमि: एक दशक का निर्णायक मोड़

वर्ष 2004 से 2014 के बीच का दशक नक्सली हिंसा का चरम काल था। गृह मंत्रालय के ऐतिहासिक रिकॉर्ड के अनुसार, इस अवधि में नक्सली हिंसा की **16,463 से अधिक घटनाएं** दर्ज की गईं। लेकिन 2014 के बाद नीतिगत दृष्टिकोण में आए 'पैराडाइम शिफ्ट' (अमूल-चूल परिवर्तन) ने इस खूनी सिलसिले पर नकेल कसना शुरू किया। 2014 से 2024 के बीच हिंसक घटनाएं 53% घटकर 7,744 रह गईं और सुरक्षा बलों की शहादत में 73% की ऐतिहासिक कमी आई।

सुरक्षा बलों और गृह मंत्रालय की संयुक्त रणनीतियों की बदौलत आज (2026 में) लाल गलियारा इतिहास के पन्नों में सिमट चुका है। इसे नीचे दी गई ऐतिहासिक तुलनात्मक तालिका से भली-भांति समझा जा सकता है:

सुरक्षा एवं भौगोलिक संकेतक	**चरम काल (वर्ष 2010)**	**नीतिगत बदलाव (वर्ष 2014)**	**वर्तमान स्थिति (वर्ष 2026)**	**ऐतिहासिक गिरावट / सुधार**
कुल प्रभावित जिले	126 से 180 जिले	126 जिले	**मात्र 11 जिले**	**लगभग 92% का भौगोलिक संकुचन**
अत्यधिक प्रभावित 'हॉटस्पॉट' जिले	36 जिले	30+ जिले	**मात्र 3 जिले** *(बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर)*	**नक्सलवाद अब अंतिम गढ़ों में सिमटा**
वार्षिक हिंसक घटनाएं	1,936 घटनाएं	1,091 घटनाएं	**222 घटनाएं** *(नवीनतम वार्षिक*	**89% की भारी गिरावट**

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 16 Issue 06, June 2026,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081 UGC Approved Journal Number: 48887
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

सुरक्षा एवं भौगोलिक संकेतक	चरम काल (वर्ष 2010)	नीतिगत बदलाव (वर्ष 2014)	वर्तमान स्थिति (वर्ष 2026)	ऐतिहासिक गिरावट / सुधार
			डेटा)	
नागरिक एवं बलों की मृत्यु	1,005 मौतें	384 मौतें	**95 मौतें**	**91% की ऐतिहासिक कमी**
फोर्टिफाइड (किलेनुमा) पुलिस स्टेशन	अत्यंत नगण्य	66 पुलिस स्टेशन	**612+ पुलिस स्टेशन**	**सुरक्षा ढांचे का अभूतपूर्व सुदृढ़ीकरण**
अग्रिम सुरक्षा शिविर (Forward Camps)	शून्य (रक्षात्मक मुद्रा)	सीमित संख्या	**400 से अधिक नए अग्रिम शिविर**	**नक्सलियों की 'नो-गो जोन' मांद में प्रवेश**

संसद में पेश किए गए हालिया आंकड़ों (फरवरी और मार्च 2026) के अनुसार, वामपंथी उग्रवाद अब इतिहास के पन्नों में सिमटने को है:

संकेतक	वर्ष 2010 (चरम सीमा)	वर्ष 2025 - 2026	गिरावट (%) / वर्तमान स्थिति
प्रभावित जिले	126 जिले	मात्र 8 से 11 जिले	**90%+ का संकुचन**
गंभीर रूप से प्रभावित जिले	36 जिले	मात्र 3 जिले (बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर)	**अब केवल आखिरी गढ़ शेष**
हिंसक घटनाएं	1,936 घटनाएं	234 घटनाएं (2025)	**88% की भारी गिरावट**
नागरिक एवं बलों की मृत्यु	1,005 मृत्यु	100 मृत्यु (2025)	**90% की कमी**
हिंसा दर्ज करने वाले थाने	465 पुलिस स्टेशन	119 पुलिस स्टेशन	**भौगोलिक रूप से सीमित**

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 16 Issue 06, June 2026,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081 UGC Approved Journal Number: 48887
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

- **नेतृत्व विहीन संगठन:** वर्ष 2024 और 2025 में सुरक्षा बलों ने अभूतपूर्व सफलता पाते हुए माओवादियों के शीर्ष पोलित ब्यूरो और केंद्रीय समिति के 6 से अधिक सदस्यों सहित बड़े कमांडरों (जैसे नंबाला केशवराव उर्फ बसवराजू) को निष्प्रभावी कर दिया है।

- **ऐतिहासिक आत्मसमर्पण:** अकेले वर्ष 2025 में **2,337 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण** किया। यह दर्शाता है कि कैडरों का वैचारिक और मानसिक मनोबल पूरी तरह टूट चुका है।

5. संसदीय बहसें और गृह मंत्री के वक्तव्य: एक दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति

संसद के पटल पर और हालिया राष्ट्रीय मंचों (जैसे *'भारत मंथन-2025: नक्सल मुक्त भारत'*) पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयानों ने सरकार के संकल्प को देश के सामने रखा है।

संसद और सार्वजनिक मंचों पर दिए गए मुख्य वक्तव्य:

- **लोकसभा और राज्यसभा (फरवरी-मार्च 2026) में गृह मंत्री ने कहा:** *"कश्मीर, पूर्वोत्तर और नक्सलवाद—ये देश की आंतरिक सुरक्षा के तीन सबसे बड़े हॉटस्पॉट थे। तीन पीढ़ियां इस दुष्चक्र में बर्बाद हो गईं। मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि हमारे वीर जवानों के बलिदान और सुदृढ़ नीति के कारण आज भारत नक्सलवाद के दंश से लगभग मुक्त हो चुका है। बस्तर में अब बंदूक नहीं, विकास की गूंज है।"*
- **विकास विरोधी नैरेटिव पर कड़ा प्रहार:** संसद में विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए गृह मंत्री ने उन बुद्धिजीवियों को आड़े हाथों लिया जो नक्सलवाद को 'केवल विकास की कमी' का परिणाम बताते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया: *"प्रधानमंत्री मोदी ने 60 करोड़ गरीबों के लिए योजनाएं भेजीं, लेकिन बस्तर और सुकमा में स्कूल-सड़कें क्यों नहीं बनने दी गईं? क्योंकि नक्सलियों ने ठेकेदारों और निर्दोष आदिवासियों की हत्या की। जो हथियार उठाएगा, उसे सुरक्षा बलों के कड़े जवाब का सामना करना पड़ेगा; जो मुख्यधारा में आएगा, उसके लिए सरकार पलकें बिछाकर तैयार है।"*
- **बस्तर 2.0 रोडमैप (मई 2026):** हाल ही में गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ के जगदलपुर और बस्तर का दौरा कर **"बस्तर 2.0 रोडमैप"** लॉन्च किया, जिसके तहत जंगलों में बने सुरक्षा कैंपों को अब 'जन सुविधा केंद्रों' (Public Utility Centers) में बदला जा रहा है ताकि नक्सलवाद दोबारा कभी सिर न उठा सके।

6. विकास का इंजन और समावेशन की राजनीति

5. विकास का इंजन और समावेशन की राजनीति: ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और धरातली जुड़ाव

वामपंथी उग्रवाद (LWE) के खिलाफ भारत सरकार की सफलता का एक सबसे बड़ा कारण सैन्य कार्रवाई के साथ-साथ 'समावेशन की राजनीति' और 'कल्याणकारी राज्य' (Welfare State) की अवधारणा को सुदूर जंगलों तक पहुंचाना रहा है। ऐतिहासिक रूप से, नक्सलवाद ने उन क्षेत्रों में अपनी जड़ें जमाईं जो भौगोलिक रूप से कटे हुए थे और जहां विकास की किरण नहीं पहुंच पाई थी। माओवादियों ने आदिवासियों के इसी अलगाव, भूमि अधिकारों की अनिश्चितता और बुनियादी सुविधाओं के अभाव को अपनी ढाल बनाया था।

इस ऐतिहासिक भूल को सुधारने के लिए, केंद्र सरकार ने एक द्वि-आयामी रणनीति (Twin-Track Strategy) अपनाई—"अंतिम छोर तक सुरक्षा और अंतिम व्यक्ति तक विकास"। इसका मुख्य उद्देश्य

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 16 Issue 06, June 2026,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081 UGC Approved Journal Number: 48887
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लोगों में व्यवस्था के प्रति विश्वास बहाल करना और उन्हें देश की मुख्यधारा से जोड़ना था।

- **भौगोलिक अलगाव का अंत (सड़कों का जाल):** माओवादियों के हिंसक विरोध और ठेकेदारों पर हमलों के बावजूद, 'रोड रिक्वायरमेंट प्लान' (RRP) और 'वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र सड़क योजना' के तहत अब तक **15,016 किलोमीटर से अधिक लंबी ऑल-वेदर सड़कों** का निर्माण दुर्गम वनों और पहाड़ों को काटकर किया जा चुका है। इन सड़कों ने सुरक्षा बलों की गतिशीलता को तो बढ़ाया ही, साथ ही ग्रामीणों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और बाजारों तक पहुंच को सुलभ कर दिया।
- **डिजिटल और वित्तीय समावेशन (Financial and Digital Inclusion):** पूर्व में इन क्षेत्रों में वित्तीय संस्थाओं की कमी के कारण नक्सली समानांतर अर्थव्यवस्था (जबरन वसूली और लेवी) चलाते थे। सरकार ने वित्तीय समावेशन के तहत डिजिटल कनेक्टिविटी को प्राथमिकता दी, जिसके लिए **9,233 से अधिक मोबाइल टावर** स्थापित किए जा चुके हैं। इसके साथ ही, बैंकिंग सेवाओं को गांवों तक पहुंचाने के लिए डाक विभाग ने **6,025 से अधिक पोस्ट ऑफिस** और वाणिज्यिक बैंकों ने सुदूर क्षेत्रों में 1,800 से अधिक शाखाएं व 1,321 ATMs स्थापित किए हैं। इसके परिणामस्वरूप, अब कल्याणकारी योजनाओं का पैसा सीधे 'डीबीटी' (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से बिना किसी बिचौलिये या नक्सली हस्तक्षेप के सीधे आदिवासियों के खातों में पहुंच रहा है।
- **शिक्षा और कौशल से वैचारिक परिवर्तन:** युवाओं को बंदूक की संस्कृति से दूर करने के लिए शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार बनाया गया। जनजातीय और सुदूर क्षेत्रों के बच्चों के लिए **179 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS)** पूरी तरह चालू किए गए हैं, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, 'रोनी' (Roshni) जैसी विशेष कौशल विकास योजनाओं के तहत 46 ITI और 49 कौशल विकास केंद्र स्थापित किए गए हैं, जो स्थानीय युवाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण देकर देश के औद्योगिक विकास का हिस्सा बना रहे हैं।

इस बहुआयामी समावेशन नीति ने नक्सलियों के उस नैरेटिव को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया, जिसमें वे सरकार को 'आदिवासी विरोधी' बताते थे। जब आदिवासियों को सीधे विकास, शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण का लाभ मिलने लगा, तो माओवादियों का स्थानीय जन-समर्थन आधार पूरी तरह समाप्त हो गया।

सैन्य कार्रवाई के साथ-साथ इन क्षेत्रों में सरकार ने विकास को संतृप्ति (Saturation) के स्तर तक पहुंचाया है:

- **सड़कों का जाल:** 'रोड रिक्वायरमेंट प्लान' (RRP) के तहत अब तक **15,016 किलोमीटर से अधिक लंबी ऑल-वेदर सड़कों** का निर्माण दुर्गम वनों में किया जा चुका है।
- **डिजिटल और वित्तीय समावेशन:** संचार क्रांति के तहत **9,233 से अधिक मोबाइल टावर** स्थापित किए जा चुके हैं। वित्तीय समावेशन के लिए डाक विभाग ने **6,025 से अधिक पोस्ट ऑफिस** और बैंकों ने सुदूर क्षेत्रों में 1,800 से अधिक शाखाएं व 1,321 ATMs स्थापित किए हैं ताकि सीधे 'डीबीटी' (Direct Benefit Transfer) का लाभ आदिवासियों तक पहुंचे।
- **शिक्षा और कौशल:** जनजातीय बच्चों के लिए **179 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS)** चालू किए गए हैं। साथ ही 'रोशनी' जैसी कौशल विकास योजनाओं के तहत 46 ITI और 49 कौशल विकास केंद्र युवाओं को मुख्यधारा के रोजगार से जोड़ रहे हैं।
- **7. नई वैचारिक चुनौती: 'शहरी नक्सलवाद'**
- जैसे-जैसे ग्रामीण अंचलों में नक्सलियों की बंदूकें शांत हुई हैं, सरकार का ध्यान अब एक नई और छिपी हुई चुनौती की ओर गया है, जिसे **'शहरी नक्सल' (Urban Naxals)** कहा जाता है।

- गृह मंत्रालय के हालिया दस्तावेजों के अनुसार, माओवाद केवल एक सशस्त्र आंदोलन नहीं बल्कि एक 'विनाशकारी विचार' है। कुछ तत्व शहरों, विश्वविद्यालयों, अकादमिक संस्थानों और छद्म गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) में बैठकर इस हिंसक विचारधारा को बौद्धिक संरक्षण, कानूनी कवच और रसद प्रदान करते हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जब तक इस वैचारिक और सूचना-युद्ध (Information Warfare) के तंत्र को पूरी तरह ध्वस्त नहीं किया जाता, तब तक यह लड़ाई अधूरी है। इसी रणनीति के तहत सरकार अब इनके वैचारिक इकोसिस्टम को कानून के दायरे में लाकर समाप्त कर रही है।

निष्कर्ष: एक नए, सुरक्षित भारत का अभ्युदय

- नक्सलवाद का आसन्न खात्मा केवल एक सुरक्षात्मक जीत नहीं है, बल्कि यह भारत के लोकतांत्रिक सिद्धांतों, न्याय व्यवस्था और संविधान की सबसे बड़ी विजय है। यह उन करोड़ों आदिवासियों की जीत है जिन्हें दशकों तक 'लाल गलियारे' में भय और वंचना के साए में बंधक बनाकर रखा गया था।
- आज बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर जैसे क्षेत्रों में विकास की नई सुबह हो चुकी है। सरकार ने 'लेगेसी एंड थ्रस्ट डिस्ट्रिक्ट्स' (Legacy and Thrust Districts) नामक नई श्रेणी बनाकर यह सुनिश्चित किया है कि जिन 30 जिलों से नक्सलवाद खत्म हो चुका है, वहां दोबारा यह बीमारी न पनप सके। भारत का 2026 का यह संकल्प कि वह पूर्णतः नक्सल-मुक्त होगा, न केवल आंतरिक सुरक्षा के लिए बल्कि देश को वैश्विक महाशक्ति बनाने के पथ पर एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। यह अंत का युग नहीं, बल्कि एक सुरक्षित, समृद्ध और समरस भारत का नया सवेरा है।

संदर्भ सूची (References)

1. Glasgow RE, Vogt TM, Boles SM. Evaluating the public health impact of health promotion interventions: the RE-AIM framework. *Am J Public Health.* (1999) 89:1322–7. doi: 10.2105/AJPH.89.9.1322
2. Ministry of Home Affairs (MHA). Annual Report and Left-Wing Extremism (LWE) Division Statistical Dashboard (2010–2026). *Government of India.* (2026). Available online at: https://www.mha.gov.in/
3. Parliament of India. Parliamentary Proceedings and Ministerial Statements on Internal Security: Budget Session 2026. *Sansad TV Records.* (2026) Lok Sabha & Rajya Sabha Archives.
4. Tabak RG, Khoong EC, Chambers DA, Brownson RC. Bridging research and practice: models for dissemination and implementation research. *Am J Prev Med.* (2012) 43:337–50. doi: 10.1016/j.amepre.2012.05.024
5. Manohar Parrikar Institute for Defence Studies and Analyses (MP-IDSA). The Collapse of the Maoist Movement in India: Internal Security Challenges and Strategic Policy Shift (2024–2026). *Strategic Policy Paper.* (2026) 14:102–115.
6. Ministry of Tribal Affairs & MoRTH. Infrastructure Saturation and Eklavya Model Residential Schools (EMRS) Progress Report 2025–26. *Government of India.* (2026).
7. Shoup JA, Gaglio B, Varda D, Glasgow RE. Network analysis of RE-AIM framework: chronology of the field and the connectivity of its contributors. *Transl Behav Med.* (2015) 5:216–32. doi: 10.1007/s13142-014-0300-1
8. Vivekananda International Foundation (VIF). Counter-Maoist Operations: The Tactical Role of Forward Security Camps and Inter-State Coordination. *Internal Security Studies.* (2025) 8:44–66.

9. Kessler RS, Purcell EP, Glasgow RE, Klesges LM, Benkeser RM, Peek CJ. What does it mean to "employ" the RE-AIM model? *Eval Health Prof.* (2013) 36:44–66. doi: 10.1177/0163278712446066
10. Department of Telecommunications (DoT) & Department of Financial Services (DFS). Joint Report on Digital Connectivity and Direct Benefit Transfer (DBT) Penetration in LWE Affected Districts. *Ministry of Communications, GoI.* (2026).
11. Vinson C, Stamatakis K, Kerner J. Dissemination and implementation research in community and public health settings. In: Brownson RC, Colditz GA, Proctor EK, editors. *Dissemination and Implementation Research in Health: Translating Research to Practice.* Oxford, NY: Oxford University Press (2018). p. 355–70.
12. Ministry of Home Affairs (Internal Security Wing). Urban Left-Wing Extremism: Ideological Networks, Information Warfare, and Legal Enforcement Framework. *Government of India Manual.* (2025) Article 64.